

NHRC for CBI probe into West Bengal post-poll violence

PNS ■ KOLKATA

Asserting that the situation in West Bengal is a "manifestation of law of ruler instead of rule of law", an NHRC committee probing alleged incidents of post-poll violence in the state, in a report placed before the Calcutta High Court, has recommended a CBI probe into "grievous offences like murder and rape".

The committee, which was formed by the National Human Rights Commission (NHRC) chairman on a direction by a five-judge bench of the high court, also said that these cases should be tried outside the state.

"The spatio-temporal expanse of violent incidents in the state of West Bengal reflects the appalling apathy of the state government towards plight of victims.

"The committee has recommended that grievous offences like murder, rape, etc should be handed over to the CBI for



investigation and these cases should be tried outside the state," the report, submitted before the court on June 13, said.

A bunch of PILs filed before the high court alleged that people were subjected to assault, made to flee homes, and property were destroyed as a result of post-poll violence in Bengal.

"This was retributive violence by supporters of the ruling party against supporters of the main opposition party," the NHRC committee said in its scathing remarks.

चुनाव बाद हिंसा : मानवाधिकार आयोग ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, कहा- बंगाल में कानून का राज नहीं, शासक का कानून

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई हैं। राज्य में हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के बावजूद ममता सरकार के इनकार के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कानून का शासन नहीं, बल्कि एक शासक का कानून चलता है। आयोग ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के निर्देश पर गठित मानवाधिकार आयोग की समिति ने



राजनीतिक बदले की भावना से किया पक्षपाती एजेंसी का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक बदले की भावना से राज्य को बदनाम करने के लिए पक्षपाती एजेंसी का इस्तेमाल किया है। एनएचआरसी को भीड़िया में रिपोर्ट लीक करने के बजाय कोर्ट का सम्मान करते हुए पहले उसे रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी। -ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल



इन सभी मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में भयानक हिंसा पीड़ितों की दुर्दशा के

प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा

था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एजेंसी

आयोग की अहम सिफारिशें

- चुनाव बाद हिंसा मामलों की सीबीआई जांच हो। सभी मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर हो, भारी हिंसा से पता चलता है कि राज्य सरकार ने पीड़ितों के प्रति भयानक उदासीनता दिखाई।
- साफ पता चलता है कि चुनाव में भाजपा को समर्थन देने के लिए बदले की कार्रवाई की गई, अधिकारी हिंसा की घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ घटनाओं में खुद भी शामिल रहे।

मानवाधिकार आयोग ने पेश की रिपोर्ट



संजाल हिता

भारत में जहाँ, पृथ्वी में जहाँ
का राज पृथ्वी का ही है नाश

लोदी ने यूपी में जलंध के लिए
किताने कम्प्लेक्स भेजे हैं, समझा

**दिल्ली में राष्ट्रपति व पीएम
को मालाकारों का नुस्खे लगाऊंगी**

[illegible][illegible]

चुनाव बाद हिंसा पर घिरी ममता सरकार

मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट से कहा- बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून

कोलकाता। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद गंभीर रिपोर्ट सब्मिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। इस बीच, 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट के कुछ न्यूज चैनल और वेबसाइट्स पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऐतराज जाहिर किया है। ममता ने कहा कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए।

आयोग ने रिपोर्ट में यह कहा



1. बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराधों की जांच होनी चाहिए।
2. बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयानक तरीके से उदासीनता दिखाई है।
3. हिंसा से जाहिर होता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से हुई है। ये उन लोगों से बदला लेने के लिए की गई, जिन्होंने चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को समर्थन देने की जुरत की।
4. राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ इन हिंसक घटनाओं में खुद शामिल रहे हैं।

चुनाव बाद हिंसा : मानवाधिकार आयोग ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, कहा- बंगाल में कानून का राज नहीं, शासक का कानून

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई हैं। राज्य में हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के बावजूद ममता सरकार के इनकार के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कानून का शासन नहीं, बल्कि एक शासक का कानून चलता है। आयोग ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के निर्देश पर गठित मानवाधिकार आयोग की समिति ने



राजनीतिक बदले की भावना से किया पक्षपाती एजेंसी का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक बदले की भावना से राज्य को बदनाम करने के लिए पक्षपाती एजेंसी का इस्तेमाल किया है। एनएचआरसी को भीड़िया में रिपोर्ट लीक करने के बजाय कोर्ट का सम्मान करते हुए पहले उसे रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी। -ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल



इन सभी मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में भयानक हिंसा पीड़ितों की दुर्दशा के

प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा

था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एजेंसी

आयोग की अहम सिफारिशें

- चुनाव बाद हिंसा मामलों की सीबीआई जांच हो। सभी मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर हो, भारी हिंसा से पता चलता है कि राज्य सरकार ने पीड़ितों के प्रति भयानक उदासीनता दिखाई।
- साफ पता चलता है कि चुनाव में भाजपा को समर्थन देने के लिए बदले की कार्रवाई की गई, अधिकारी हिंसा की घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ घटनाओं में खुद भी शामिल रहे।

NHRC recommends CBI probe on Bengal post-poll violence

Press Trust of India

letters@hindustantimes.com

KOLKATA: Asserting that the situation in West Bengal is a "manifestation of law of ruler instead of rule of law", an NHRC committee probing alleged incidents of post-poll violence in the state, in a report placed before the Calcutta High Court, has recommended a Central Bureau of Investigation (CBI) probe into "grievous offences like murder and rape".

The committee, which was formed by the National Human Rights Commission (NHRC) chairman on a direction by a five-judge bench of the high court, also said that these cases should be tried outside the state.

"The spatio-temporal expanse of violent incidents in the state of West Bengal reflects the appalling apathy of the state government towards plight of victims. The committee has recommended that grievous offences like murder, rape, etc should be handed over to the CBI for investigation and these cases should be tried outside the state," the report, submitted before the court on June 13, said.

A bunch of PILs filed before the high court alleged that people were subjected to assault, made to flee homes, and property were destroyed as a result of

**CHIEF MINISTER
MAMATA BANERJEE
THURSDAY FLAYED
THE NHRC FOR
'DISRESPECTING
THE COURT' AND
LEAKING THE
REPORT TO MEDIA**

post-poll violence in Bengal.

"This was retributive violence by supporters of the ruling party against supporters of the main opposition party," the NHRC committee said in its scathing remarks.

Meanwhile, West Bengal chief minister Mamata Banerjee Thursday flayed the NHRC for "disrespecting the court" and pursuing "political vendetta" of the BJP by leaking its report on alleged post-poll violence to the media. Banerjee also expressed surprise over the conclusion that the National Human Rights Commission arrived at in its report without taking into account views of the state government.

"What would you call it other than political vendetta of the BJP? It is yet to digest defeat (in the assembly polls) and that is why the party is resorting to such tricks," she told a press conference here.

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच हो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति ने कलकत्ता हाईकोर्ट को 13 जून को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में राज्य में स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन करार देते हुए हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने यह भी कहा कि इन मामलों में मुकदमे राज्य से बाहर चलने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्पूरता को दर्शाता है। याचिकाओं में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में लोगों पर हमले किए गए जिससे उन्हें घर छोड़ने पड़े।

बंगाल में 'कानून का राज' नहीं, 'शासक का कानून' चल रहा: एनएचआरसी

कोलकाता/एक्शन इंडिया ब्यूरो
बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(एनएचआरसी) की ओर से
कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी गई।
अंतिम रिपोर्ट में राज्य प्रशासन की
कड़ी आलोचना की गई है 50 पेज
की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि
राज्य प्रशासन ने जनता में अपना
विश्वास खो दिया है। टीम ने सख्त
टिप्पणी करते हुए कहा है कि
कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की धरती
बंगाल में 'कानून का राज नहीं' है
बल्कि यहां 'शासक का कानून'
चल रहा है। रिपोर्ट में चुनाव बाद
हिंसा की जांच सीबीआई से कराने
की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट बंगाल चुनाव हिंसा मामले में रेप व हत्याओं की सी.बी.आई. जांच हो

कोलकाता, 15 जुलाई (एजेंसी): पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) समिति ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में 'हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों' की जांच सी.बी.आई. से कराए जाने और इन मामलों में मुकद्दमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की है। समिति ने राज्य में स्थिति को 'कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन' करार

इन मामलों में मुकद्दमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की

दिया है।

हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ के निर्देश पर एन.एच.आर.सी. अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है। कोर्ट को 13 शेष पृष्ठ 4 पर

बंगाल चुनाव हिंसा...

जून को यह रिपोर्ट सौंपी गई। हाईकोर्ट में दायर कई जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में लोगों पर हमले किए गए जिसकी वजह से उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। एन.एच.आर.सी. समिति ने अपनी बेहद तल्ख टिप्पणी में कहा, 'सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा यह हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई।'।

भाजपा के 'राजनीतिक प्रतिशोध' पर चल रही समिति : ममता : राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिपोर्ट की आलोचना की और कहा कि समिति अपने निष्कर्षों को मीडिया को लीक कर भाजपा के 'राजनीतिक प्रतिशोध' पर चल रही है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी वाली बात है कि समिति राज्य सरकार के मत को संज्ञान में लिए बिना निष्कर्ष पर पहुंच गई।

NHRC WANTS CBI PROBE, VIOLENCE CASE TO BE TAKEN OUT OF BENGAL

KOLKATA: Incidents of post-poll violence in West Bengal should be probed by the CBI and trials held outside the state, the National Human Rights Commission recommended to the Calcutta high court, slamming the state government and ruling party, and calling the clashes a “death knell” for democracy.

APPALLING APATHY | Rights Commission For CBI Probe In Bengal Post-Poll Violence

‘Political vendetta’: Mamata hits out at NHRC for ‘leaking’ report

ARITRA SINGHA
Kolkata

The final report of National Human Rights Commission (NHRC) to Calcutta High Court appeals for a CBI probe over post-poll violence.

According to court sources, the NHRC team quoted Nobel Laureate Rabindranath Tagore and said that a CBI probe is necessary to curb the bloodshed and atrocities against women in the land of Tagore.

“Where the mind is without fear and the head is held high..... the land of Tagore is witnessing murders and rapes and until a CBI probe is ordered the post-poll violence cannot be curbed,” read the report.

Talking to Free Press Journal, BJP lawyer Priyanka Tibrewal said that after the recommendation of NHRC in their report it is clear that my allegation and claims on post-poll violence is true.

“This state is spiteful of gruesome killings and rapes. The NHRC report states that there are 28 murders so far. A CBI probe is extremely necessary to curb



WHAT MAMATA SAID

“What would you call it other than political vendetta of the BJP? It is yet to digest defeat (in the assembly polls) and that is why the party is resorting to such tricks,” “PM Modi knows very well that there is no rule of law in UP. How many human rights commission has he sent there?...So many incidents, from Hathras to Unnao, have taken place.”

WHAT NHRC SAID

“To compound the problem, violence and intimidation has continued. There is palpable fear among victims against police and goons of ruling party. Many displaced persons have not yet been able to return to their homes and resume their normal life and livelihood. There have been several sexual offences but victims are scared to speak out.”

MAMATA WRATH Mamata on Thursday lashed out at the National Human Rights Commission after its committee, probing alleged incidents of post-poll violence in the state, accused the state government of showing “appalling apathy” towards the victims of the post-poll violence. Banerjee accused the committee of leaking its probe report to media and called the move a “political vendetta.”

the violence. The Chief Minister Mamata Banerjee is in denial mode but the displaced workers should be rehabilitated at the expense of the state,” said Tibrewal.

Notably, even on Thursday West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee claimed that BJP is giving distorted facts and is misleading the people on Post-poll violence and also that there were incidents of little pre-poll violence when the Election Commission was in charge of the state.

Reacting to this, Tibrewal said that the committee that was formed by Calcutta High Court that reviewed post-poll violence in West Bengal included people from West Bengal legal authority and West Bengal Human Rights Commission.

“Is the Chief Minister trying to say that the state counterpart of the Human Rights and Legal Authority of West Bengal is being run by the BJP? The West Bengal police were earlier instructed to investigate the matter but they didn’t and we all know at whose behest the police didn’t work,” further mentioned the BJP lawyer.

Didi to visit Delhi to meet ‘friends’

KOLKATA: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will visit Delhi at the end of July to meet her ‘friends’.

Addressing the media, Mamata said she didn’t visit Delhi for a long time and also that since the Covid situation is better now she will visit the national capital.

“I have not been to Delhi for a long time and since the covid situation is better now I will visit my friends. If I am given an appointment then I will meet Prime Minister Narendra Modi and President Ram Nath Kovind as well,” said the West Bengal Chief Minister.

According to TMC sources, the TMC Supremo is visiting Delhi on July 25 and is expected to stay for five days.

Notably, after the landslide victory against the BJP in the recently concluded Assembly polls, many are expecting Mamata Banerjee to play a bigger role in the 2024 parliamentary election. Speculation even started that she might become the face of the opposition against BJP.

NHRC report leak political vendetta against Bengal: Didi

BJP Members Have Got Into Panel: TMC

Debashis.Konar
@timesgroup.com



CM Mamata Banerjee said the state should have been allowed to respond to the report

TMC netas threaten action against NHRC

Kolkata: Senior Trinamool leaders who have been named as “notorious criminals/goons” in the NHRC panel’s report have threatened legal action against the rights body saying they had no complaints against them in any police station in Bengal. TNN

Kolkata: Trinamool seniors on Thursday reacted to the NHRC panel’s “findings”, saying such reports were natural when “BJP activists become NHRC members”. Bengal CM Mamata Banerjee said that she knew “the people who submitted the report”.

“Only the court will give their identity,” Banerjee said, adding that she had the highest respect for the court. “I will abide by the court verdict. This is a sub-judice matter. They have leaked it instead of submitting the report in court,” she said, calling the “leak” an act of “political vendetta to malign the people of Bengal”.

“The state government should have been allowed to

respond (to the NHRC report). The court has asked the state to give its opinion and it will be done in the form of an affidavit,” Banerjee said.

हिंसा पर घिरी ममता सरकार

NHRC की रिपोर्ट | राज्य में कानून का शासन
हाईकोर्ट में पेश नहीं, 'शासक' का कानून

महानगर नेटवर्क

कोलकाता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें कहा गया है कि राज्य में हिंसक घटनाओं में पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता है, राज्य में कानून का शासन नहीं चलता बल्कि शासक का कानून चलता है। हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर या सीबीआई से कराई जानी चाहिए।



आयोग ने कहा है कि यह मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई प्रतिशोधात्मक हिंसा थी। इसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों के जीवन और आजीविका में बाधा उत्पन्न की गई और उनका आर्थिक रूप से गला घोट दिया गया।

रिपोर्ट को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि अदालत में इसकी रिपोर्ट जमा करने के बजाय उन्होंने इसे लीक कर दिया है। उन्हें अदालत का सम्मान करना चाहिए। यदि यह राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो वे रिपोर्ट कैसे लीक कर सकते हैं?

आयोग की रिपोर्ट के चार सबसे अहम बिंदु

1. बंगाल चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराधों की जांच होनी चाहिए।
2. बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयानक तरीके से उदासीनता दिखाई है।
3. हिंसा के मामलों से जाहिर होता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से हुई है। ये उन लोगों से बदला लेने के लिए की गई, जिन्होंने चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को समर्थन देने की जुर्रत की।
4. राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं में मूक दर्शक बने रहे और कुछ इन हिंसक घटनाओं में खुद शामिल रहे हैं।

वे ऐसा करके बंगाल के लोगों को बदनाम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि अब जब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं तब मैं अब संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाऊंगी और वहां कुछ नेताओं से मिलूंगी। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलने का समय देते हैं तो मैं उनसे भी मिलूंगी।

‘Law of ruler, not rule of law’: NHRC report on WB violence

A National Human Rights Commission (NHRC) committee tasked with probing allegations of post-poll violence in West Bengal has recommended a CBI investigation into “grievous offences like murder and rape”, saying the situation in the state was a “manifestation of the law of ruler instead of rule of law”.

► **Political vendetta to malign people: Didi, P 7**

In its report tabled before the Calcutta HC, the panel, formed by the NHRC chairman on directions of the court, also suggested that trial of cases related to the violence be held outside Bengal, **reports Swati Mathur.**

The panel noted that close to 2,000 complaints had been received from 23 districts, with around 35% related to murder or homicide and 4% to rape.

► **‘State patronage’, P 7**

WB violence report: Criminals enjoyed state patronage

► From P 1

The percentage of those arrested or in those still in custody is “abysmally low” as less than 3% of the accused are in jail. There were several instances of physical intimidation of women, who were on occasion stripped and humiliated.

“Analysis of statements recorded of the victims/complainants, supporting documents, data and other related information collected from the spot enquiries, including camp sittings, registered cases, etc., revealed that a large number of criminals, who enjoy state patronage and support, were responsible for abetting, planning, organising and even committing offences in a systematic and widespread manner,” the NHRC report states.

While the report drew WB CM Mamata Banerjee’s ire, NHRC countered the allegations as “absolutely baseless and fac-

tually incorrect”.

The commission said the committee submitted its report to the HC on July 13. “On the further directions of the Hon’ble Court, the Committee provided a copy of the said report to its Advocate in Calcutta, who shared with the Advocates of all the concerned parties in the related multiple writ petitions.”

In its report, the committee referred to “spatio-temporal expanse of violent incidents in the state of West Bengal reflects the appalling apathy of the state government towards plight of the victims.”

It further noted that “The committee has recommended that grievous offences like murder, rape, etc should be handed over to the CBI for investigation and these cases should be tried outside the state.”

The committee also referred to the post-poll violence as “retributive violence by supporters of the ruling party.”

NHRC report on violence sparks political slugfest

‘No rule of law in state, let CBI probe grievous offences’

Subrata Chatteraj

Kolkata: The National Human Rights Commission (NHRC) panel examining post-poll violence complaints has said “the law of the ruler” exists in Bengal “instead of the rule of law”.

The panel, asked to examine the complaints by a five-judge bench of the Calcutta High Court, has recommended in its final report that complaints of “grievous offences like rape and murder” be handed over to the CBI for investigation. “These cases should be tried outside the state. The other cases should be investigated by a court-monitored special investigation team. There should be fast-track courts, a special public prosecutor and a witness-protection scheme,” its report stated.

The panel provided a list of 13 “delinquent police stations” in Cooch Behar, Birbhum, South 24 Parganas, North 24 Parganas and Howrah where the number of arrests was the lowest and recommended action against “delinquent government servants”.

The Bengal government has already filed a “recall application” in the Calcutta High Court, seeking modification of the five-judge bench’s order as the court gave additional directions to the state government based on the NHRC team’s “brief report” even though the state did not have access to the contents of the report.

► Panel members made 311 spot visits, P 7

its response to post-pol complaints as “lukewarm”. “The findings in the interim report are required to be supported by evidence and reasons,” the state application stated.

The NHRC report comes at a time when the Supreme Court has issued notices to the Election Commission, the Centre and the Bengal government following a PIL urging president’s rule in Bengal. The 50-page report noted the state government’s “appalling apathy” to victims’ plight, adding: “The spate of violence shows a pernicious politico-bureaucratic-criminal nexus. This was retributive violence by

still in custody “abysmally low”. The NHRC panel sent 582 complaints to the state director-general of police, following which 137 FIRs were registered; it noted 188 instances from its 311 spot visits in which no FIR was registered.

National Commission for Women member and NHRC panel member Rajuben L Desai said she found during her visit to three districts that women victims had “come under pressure from the local police to withdraw their complaints”.

50-PAGE REPORT

supporters of the ruling party against supporters of the main opposition party. It resulted in disruption of life and livelihood of thousands of people and their economic strangulation. The local police have been grossly derelict if not complicit in this violence.”

NHRC should not have leaked report: Mamata

NHRC panel invokes Tagore, indicts Mamata government

Kolkata, July 15: The situation prevailing in West Bengal is a manifestation of "law of the ruler" and not "rule of law", the NHRC panel probing alleged post-poll violence in the state has said in a damning indictment of the Mamata Banerjee government, and recommended CBI investigation in cases of rape and murder.

A livid Banerjee promptly hit back, accusing the National Human Rights Commission (NHRC) of pursuing BJP's "political vendetta" and claiming the report was "leaked".

The NHRC panel, constituted following an order by a five-judge bench of the Calcutta High Court, also said the cases of alleged rape and murder be tried outside the state.

"The committee has recommended that grievous offences like murder, rape, etc should be handed over to the CBI for investigation and these cases should be tried outside the state," the report, submitted to the court in sealed covers on June 13, said.

"The situation in the State of West Bengal is a manifestation of 'Law of Ruler' instead of 'Rule of Law,' the report of the seven-member committee said, as it highlighted "appalling apathy" of the government towards the plight of victims.

After the report was submitted on Tuesday, the court had directed that its soft copies along with annexures be supplied to the counsel for the petitioners, the Election Commission, and the Additional Solicitor General of India.

Banerjee, however, cried foul and claimed the report was leaked to the media by the rights panel. She also said the NHRC team did not consult the

Mamata to hold talks with non-BJP leaders

Kolkata, July 15: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is likely to visit New Delhi later this month where she will hold talks with leaders of non-BJP parties, TMC sources said on Thursday, amid the renewed buzz over formation of an anti-BJP front ahead of the 2024 Lok Sabha polls.

According to some reports, she will head to the national capital on July 25.

Sources in West Bengal's ruling TMC said the party supremo's Delhi visit could happen any day after the Martyr's Day rally in Kolkata on July 21.

The talk of an anti-BJP front got revived after leaders of various parties and prominent individuals congregated at NCP chief Sharad Pawar's New Delhi residence last month.

However, there was no tangible movement forward in that direction at the meeting hosted by Pawar and called by former union minister Yashwant Sinha, who is



Mamata Banerjee

now in the TMC. Sinha, a former BJP stalwart, is a strident critic of Prime Minister Narendra Modi.

The speculation about an anti-BJP coalition grew again after election strategist Prashant Kishor had a string of meetings with Pawar and the Gandhis, including the one he had with Congress president Sonia Gandhi, former party chief Rahul Gandhi and general secretary Priyanka Vadra together.

Though what exactly transpired at the parleys is not known yet, media speculated a broad-based coalition against the Centre's ruling NDA might have been on the agenda. —PTI

rights violation during the violence that lasted several days.

"This was retributive violence by supporters of the ruling party against supporters of the main opposition party," the NHRC panel said in the report.

"It is indeed ironical that, in the land of Rabindra Nath Tagore, 'Where the mind is without fear and the head is held high; where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls'; thousands of its citizens have been subjected to murder, rape, displacement and intimidation, etc. in the last couple of months," it noted.

The report also spoke of government machinery being used to further the objectives of the party in power.

"This may well be death knell for democracy in this great nation. It is high time that the rot is stemmed and this trend is reversed in the interest of having a vibrant democracy in this nation," the committee said in the strongly-worded 50-page report.

It warned that if the worrisome trend was not checked the "disease" may spread to other states also.

Maintaining that the acts of violence resulted in disruption of life and livelihood of thousands of people and their "economic strangulation", the report said, "The local police has been grossly derelict, if not complicit, in this violence."

Holding that violence and intimidation has continued, the report said that there is palpable "fear among victims against police and goons of ruling party." —PTI

state government or take into account its views.

"The BJP is now using impartial agencies to settle political scores and malign our state. The NHRC should have respected the court. Instead of leaking the findings to the media, it should have first submitted the same to the court."

"What would you call it other than political vendetta of the BJP? It is yet to digest defeat (in the assembly polls) and that is

why the party is resorting to such tricks," she told a press conference.

A clutch of PILs filed before the court had alleged people were assaulted, forced to flee their homes and their properties destroyed in post-election violence.

A five-judge bench headed by Acting Chief Justice Rajesh Bindal had directed the NHRC chairman on June 18 to constitute a committee to examine all cases of alleged human

NHRC panel indicts Mamata govt over post-poll violence

STATESMAN NEWS SERVICE
KOLKATA, 15 JULY

A committee of the National Human Rights Commission set up by Calcutta High Court has recommended a CBI investigation into cases of post-poll violence in Bengal like murder and rape and trial of such cases outside the state in its final report submitted to the court.

Other cases of post-poll violence should to be dealt with by a court-monitored Special Investigation Team, the committee recommended in its 50-page report.

In a severe indictment of the Mamata Banerjee government in the state, the NHRC panel said that the situation in the state is a manifestation of "Law of Ruler", instead of "Rule of Law", and

► The NHRC committee recommended CBI investigation into cases of post-poll violence in Bengal like murder and rape and trial of such cases outside the state

► In a severe indictment of the Mamata Banerjee government in the state, the NHRC panel said that the situation in the state is a manifestation of "Law of Ruler", instead of "Rule of Law", and highlighted "appalling apathy" of the government towards the plight of victims

highlighted "appalling apathy" of the government towards the plight of victims.

A livid Miss Banerjee hit back, accusing the NHRC of pursuing the BJP's "political vendetta" and claiming the report was "leaked".

Drawing attention to the state of affairs it had come across in large swathes of the state, the NHRC panel stated, "It is indeed ironical that, in the land of Rabindra Nath Tagore, 'Where the mind is without fear and the head is

held high; where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls'; thousands of its citizens have been subjected to murder, rape, displacement and intimidation, etc. in the last couple of months."

"This was retributive violence by supporters of the ruling party against supporters of the main Opposition party," the panel said, and charged that the bureaucratic edifice in the state was complicit in various degrees,

with little effort on the part of State machinery to prevent, or control or rectify the violence.

To expedite the trial of the cases, the report recommended appointment of special public prosecutors as well as setting up fast track courts.

"Most of the violent incidents included murder, rape, molestation, assault, vandalism, looting, dispossession, arson, extortion, threat and intimidation. Pertinently, they were neither sporadic nor random; instead, they targeted specific persons (those associated with the main opposition party)," the report said.

"There have been several sexual offences but victims are scared to speak out. Loss of faith in state administration among victims is very evident," the report noted.

A large number of houses, shops and vehicles, etc. of workers of the main opposition party were vandalised and looted and water and electricity connections severed, resulting in disruption of life and livelihood of these families. Many displaced persons have not yet been able to return to their homes and resume their normal life, it said.

Miss Banerjee, crying foul, said the NHRC team did not consult the state government or take into account its views.

"The BJP is now using impartial agencies to settle political scores and malign our state. The NHRC should have respected the court. Instead of leaking the findings to the media, it should have first submitted the same to the court," she told a Press conference.

पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा

एनएचआरसी ने रेप, हत्या मामलों की सीबीआई जांच कराने को कहा

पायनियर समाचार सेवा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) समिति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की है। समिति ने राज्य में स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन करार दिया है।

वहीं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिपोर्ट की आलोचना की और कहा कि समिति अपने निष्कर्षों को मीडिया को लीक कर भाजपा के राजनीतिक प्रतिशोध पर चल रही है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी वाली बात है कि समिति राज्य सरकार के मत को संज्ञान में लिए बिना निष्कर्ष पर पहुंच गई। उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने यह भी कहा कि इन मामलों

● ममता ने की आलोचना, लगाया आरोप-समिति निष्कर्षों को मीडिया को लीक कर भाजपा के राजनीतिक प्रतिशोध पर चल रही है

में मुकदमे राज्य से बाहर चलने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है।

अदालत को 13 जून को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, समिति ने सिफारिश की है कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलना चाहिए। उच्च न्यायालय में दायर कई जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में लोगों पर हमले किए गए जिसकी वजह से उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े (शेष पेज 9)

एनएचआरसी ने...

और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। एनएचआरसी समिति ने अपनी बेहद तल्ख टिप्पणी में कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा यह हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई।

बंगाल हिंसा, रेप, हत्याओं की सीबीआई जांच की सिफारिश

**एनएचआरसी ने रिपोर्ट
हाईकोर्ट को सौंपी : ममता
सरकार पर कड़ी टिप्पणियां**

कोलकाता, (पंजाब केसरी): पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) समिति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार पर बेहद तलख टिप्पणी करते हुए राज्य में स्थिति को “कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन” करार दिया तथा “हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों” की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की है।

वहीं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाबी हमला किया और एनएचआरसी पर भाजपा के “राजनीतिक प्रतिशोध” पर चलने का आरोप लगाया तथा दावा किया



कि रिपोर्ट लीक की गई है। उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने यह भी कहा कि इन मामलों में मुकदमे राज्य से बाहर चलने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का

विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है। सात सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “पश्चिम बंगाल राज्य में स्थिति ‘कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन’ है।” अदालत को 13 जून को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, “समिति ने सिफारिश की है कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।

तृणमूल सांसदों ने छह सीटों पर उपचुनाव की मांग की

तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के एक शिष्टमंडल ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल विधानसभा की छह सीटों पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। आयोग को सौंपे जापन में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आई है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपचुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल है। तृणमूल कांग्रेस के शिष्टमंडल में छह सांसद शामिल थे। जापन में तृणमूल कांग्रेस ने कहा, “कोविड-19 के मामले अब कम से कम 17 गुना घट गए हैं और 14 जुलाई तक 831 से कम मामले ही रिपोर्ट किए गए। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में दिन-ब-दिन कमी होती जा रही है।”

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच हो

कोलकाता | एजेंसी

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति ने कलकत्ता हाईकोर्ट को 13 जून को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में राज्य में स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन करार देते हुए हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने यह भी कहा कि इन मामलों में मुकदमे राज्य से बाहर चलने चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है। याचिकाओं में

एनएचआरसी की रिपोर्ट पर ममता ने हैरानी जताई

ममता बनर्जी ने कोर्ट का अपमान करने व भाजपा का राजनीतिक बदला लेने के लिए राज्य में चुनाव के बाद कथित हिंसा संबंधी रिपोर्ट मीडिया में लीक करने को लेकर राष्ट्रीय एनएचआरसी की निंदा की। बनर्जी ने राज्य सरकार के विचार जाने बिना एनएचआरसी के निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर हैरानी जताई।

कहा गया है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में लोगों पर हमले किए गए जिससे उन्हें घर छोड़ने पड़े और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। एनएचआरसी की समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा यह हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई।'।

NHRC की कमिटी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

'रेप और हत्या के मामलों की CBI से हो जांच, राज्य के बाहर चले मुकदमा'

Poonam.Pandey
@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की कमिटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के बाद अपनी सिफारिश दी है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के जिन गांवों में हिंसा के पांच से ज्यादा मामले हुए हैं, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) लगाई जाए। कमिटी ने कोलकाता हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कोर्ट के आदेश के बाद ही यह कमिटी बनाई गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 1-10 जवानों की 500 पिकेट भी तैनात की जाती है तो यह 10 बटालियन से भी कम में हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि मकसद यह होना चाहिए कि वहां सुरक्षित माहौल दे सकें। जिससे पीड़ितों में भरोसा जागे। उन्हें वहां वापस आकर रहने के लिए सुरक्षित माहौल दे सकें।

आयोग की टीम ने सिफारिश की है कि मर्डर, अननैचुरल डेथ, रेप जैसे सभी गंभीर मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए। कई केस के बारे में कहा गया है कि उनके ट्रायल राज्य से बाहर किए जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का तुरंत गठन किया जाए जिसमें सीनियर आईपीएस अधिकारी हों। एसआईटी

आयोग की रिपोर्ट के बाद क्यों भड़की ममता?

■ 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के कुछ न्यूज चैनल और वेबसाइट्स पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऐतराज जाहिर किया है। ममता ने कहा कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए।

■ हिंसा का क्या है मामला? : इस साल 2 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में कई जगह हिंसा की खबरें आईं। इसमें दो दर्जन से अधिक मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद तुरंत एक्शन लेने का दावा किया तो होम मिनिस्ट्री ने तुरंत राज्य में टीम भेजी। इसमें घटनाओं के बारे में कई तरह के तथ्य सामने आए। कोलकाता, बर्द्धमान, वीरभूम, उत्तर 24 परगना सबसे प्रभावित इलाकों में था।

■ हाईकोर्ट भी लगा चुका है फटकार? : इससे पहले 2 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने माना था कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई। कोर्ट ने ममता सरकार को गलत ठहराते हुए कहा था कि जब लोग मारे जा रहे थे और नाबालिगों से रेप हो रहा था तो सरकार इसे नकार रही थी। हिंसा का खामियाजा भुगतने वाले लोगों के बीच बंगाल सरकार विश्वास का माहौल बनाने में नाकाम रही।



जो भी केस की जांच करेगी उसे कोर्ट मॉनिटर करे। एसआईटी जिन केस की जांच करे उनका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। 50 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की एक टीम एसआईटी के साथ अटैच की जाए जो जांच की क्वालिटी और सबूतों के इक्वटा करने पर मदद कर सके।

पीड़ितों को मिले आर्थिक सहायता : मानवाधिकार आयोग की कमिटी ने रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को तुरंत

विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करनी चाहिए तब तक पीड़ित और विटनेस को प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना चाहिए। पीड़ित जिंदगी फिर से शुरू कर सकें उन्हें आर्थिक मदद देने की सिफारिश भी रिपोर्ट में की गई है। विविटम कंपनसेशन फंड से उन्हें मदद देने के लिए कहा गया है। पीड़ितों की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ है इसलिए सभी डीएम को एक या दो टीम बनानी चाहिए जो डैमेज का अंदाजा लगा सकें।

NHRC calls for CBI probe into post-poll violence in West Bengal

PRESS TRUST OF INDIA

Kolkata, July 15

An NHRC committee tasked with the probe in post-poll violence in the State, in a report placed before the Calcutta High Court, has recommended a CBI investigation into "grievous offences like murder and rape" and suggested that these cases be tried outside the State.

The committee, which was formed by the National Human Rights Commission chairman on a direction by a five-judge bench of the high court, also claimed the situation in West Bengal is a "manifestation of law of ruler instead of rule of law".

The report, however, drew the wrath of Chief Minister Mamata Banerjee, who alleged the panel was pursuing "political vendetta" by

leaking its findings to the media.

She also expressed surprise over the conclusion that the NHRC committee arrived at without taking into account views of the State government.

The panel, which submitted its findings before the court on June 13, said in its re-

port, "Spatio-temporal expanse of violent incidents in the state of West Bengal re-

flects the appalling apathy of the State government towards plight of victims.

‘Law of ruler, not rule of law’: NHRC report on Bengal violence

A National Human Rights Commission (NHRC) committee tasked with probing allegations of post-poll violence in West Bengal has recommended a CBI investigation into “grievous offences like murder and rape”, saying the situation in the state was a “manifestation of the law of ru-

Political vendetta to malign people: Didi

BJP activists have become NHRC members, TMC said. Mamata Banerjee called the “leak” of the report an act of “political vendetta to malign Bengal’s people”. **P 15**

ler, instead of rule of law”.

In its report tabled before the Calcutta high court, the panel formed by the NHRC chairman on directions of the court, also suggested trial of cases related to the violence be held outside the state, **reports Swati Mathur.**

► 2k complaints, P 15

Close to 2k complaints received: NHRC panel

►Continued from P 1

The NHRC committee noted that a very large number of complaints had been received, close to 2,000, from 23 districts. Around 35% of the complaints related to murder or homicide and 4% to rape. The percentage of those arrested or in those still in custody is “abysmally low”. Less than 3% of the accused are in jail. There were several instances of physical intimidation of women, who were on occasion stripped and humiliated.

“Analysis of statements recorded of the victims/complainants, supporting documents, data and other related information collected from the spot enquiries, including camp sittings, registered cases, etc., revealed that a large number of criminals, who enjoy state patronage and support, were responsible for abetting, planning, organising and even committing offences in a systematic and widespread manner,” the report states.

While the report drew West Bengal CM Mamata Banerjee’s ire over the NHRC allegedly pursuing “vendetta politics” of BJP and “leaking” findings to the media, NHRC countered the allegations as “absolutely baseless and factually incorrect”.

The commission said the committee submitted its report to the HC on July 13. “On the further directions of the court, the Committee provided a copy of the said report to its Advocate in Calcutta, who shared with the Advocates of all the concerned parties in the related multiple writ petitions.”

In its report, the committee referred to “spatio-temporal expanse of violent incidents in the state of West Bengal reflects the appalling apathy of the state government towards plight of victims.” It noted that “The committee has recommended that grievous offences like murder, rape, etc should be handed over to the CBI for investigation and these cases should be tried outside the state.”

NHRC WANTS CBI PROBE, VIOLENCE CASE TO BE TAKEN OUT OF BENGAL

KOLKATA: Incidents of post-poll violence in West Bengal should be probed by the CBI and trials held outside the state, the National Human Rights Commission recommended to the Calcutta high court, slamming the state government and ruling party, and calling the clashes a "death knell" for democracy.

The panel, set up on the court's order to look into clashes in the state after elections, said: "The situation in...West Bengal is a manifestation of law of ruler, instead of rule of law..." CM Mamata Banerjee hit back, saying: "How many commissions did the PM send to Uttar Pradesh?...they are misleading people..."

→P8

NHRC calls for CBI probe into Bengal poll violence

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

KOLKATA: Incidents of post-poll violence in West Bengal should be federally probed and trials held outside the state, the National Human Rights Commission recommended to the Calcutta high court, slamming the state government and ruling party and calling the clashes a "death knell" for democracy.

The seven-member panel, set up on the high court's order in June to look into clashes in the state after election results on May 2, submitted its report to the high court on Tuesday.

It said that at least 1,934 police complaints were lodged in the state between May 2 and June 20, including 29 complaints of murder, 12 of rape and sexual assault and 940 of loot and arson. Out of the 9,304 people named as accused, less than 3% are currently in jail, found the panel. "The situation in the state of West Bengal is a manifestation of law of ruler, instead of rule of law. This was retributive violence by supporters of the ruling party against supporters of the main opposition party," said the 50-page report.

"It is indeed ironical that, in the land of Rabindranath Tagore...thousands of its citizens have been subjected to murder, rape, displacement and intimidation, etc. in the last couple of months," it added.

Chief minister Mamata Banerjee hit back at the panel, saying the report was misleading and facts distorted. "How many commissions and central agencies did the PM send to Uttar Pradesh?...they are misleading people and distorting facts," Banerjee said.

Violence broke out in various parts of the state hours after the Trinamool Congress (TMC) trounced the Bharatiya Janata Party (BJP) to secure a third consecutive term on May 2. BJP leaders alleged that they were threatened and threatened by TMC members, their houses ransacked and offices vandalised.

Key findings of NHRC report

"The situation in the state of West Bengal is a manifestation of Law of Ruler, instead of Rule of Law," the report said.

Recommendations

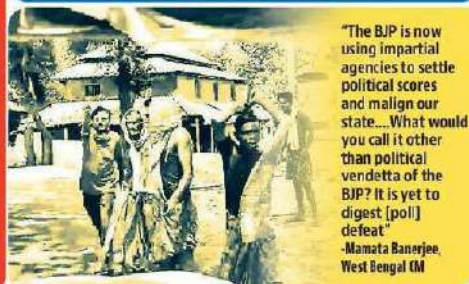
- CBI probe into complaints of murder, rape, sexual assault
- Trials of cases probed by CBI should be held outside state
- Formation of court-monitored SIT
- Setting up of fast track courts
- Witness protection scheme should be provided
- Compensation to kin of deceased and to victims of rape/sexual assault from Victims Compensation Fund
- A monitoring committee to oversee that court suggestions are implemented

1,934 Total complaints filed between May 2 and June 20

9,304
No. of accused

1,354
Arrested

1,086
Granted bail



"The BJP is now using impartial agencies to settle political scores and malign our state...What would you call it other than political vendetta of the BJP? It is yet to digest [poll] defeat"
-Mamata Banerjee, West Bengal CM

The TMC denied the charges and said that the BJP was trying to exaggerate isolated clashes.

On June 18, the high court — hearing a bunch of public interest litigation — asked NHRC to probe the violence. Three days later, it rejected the state government's review petition and said the administration's conduct didn't inspire confidence.

The NHRC committee visited at least 311 spots and found that in 60% of the places FIRs were not registered.

"Out of the 9,304 accused cited in the FIRs only 1,354 (14%) have been arrested and, out of these arrested, 1,086 (80%) are already on bail. Thus, overall speaking, less than 3% of the accused are in jail, while 97% are out in the open, making a mockery of the whole system," the report stated, adding that police didn't have the courage to take action against goons belonging to the ruling dispensation.

"Hence it is recommended that all heinous crimes, including murder, unnatural deaths, rape and grievous hurt, and complaints carrying these alle-

gations should be transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI)... Trial of all the above cases investigated by the CBI should be held outside the state," the report recommended.

It also suggested a court-monitored special investigation team with a special public prosecutor, trial in fast track courts, deployment of central forces, and reforms in police. "This may well be death knell for democracy in this great nation. It is high time that the rot is stemmed and this trend is reversed in the interest of having a vibrant democracy in this nation," the committee said.

Banerjee said the panel was trying to malign the state after the BJP's poll loss.

"How many commissions and central agencies did the PM send to Uttar Pradesh? Majority of the incidents (violence) took place when law and order was with the Election Commission. They are misleading people and distorting facts," Banerjee said.

She also said, "We will submit our opinion through an affidavit to the court when our turn comes. I am sorry to say that

instead of giving the report to the court they (NHRC) have leaked the reports. They should have respected the court. We are the government and the court is yet to hear us. Before that how can they leak the reports? It is their political vendetta."

The BJP attacked the ruling TMC. "The NHRC report is just the tip of an iceberg. The report shows where democracy is in the state. The TMC has no faith in any constitutional body," said Samik Bhattacharya, BJP spokesperson in the state.

TMC delegation meets EC seeking bypolls to 7 seats

A six member delegation of the TMC on Thursday met the full bench of the Election Commission of India in Delhi, seeking by-elections in seven assembly constituencies in West Bengal at the earliest. "A delegation of the TMC MPs met the CEC Sushil Chandra and the full bench. We have submitted a memorandum requesting that by-elections which are due in the state be held at the earliest," said Saugata Roy, TMC MP.

बंगाल में हिंसा पर आयोग ने कहा, कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है यहां

Poonam.Pandey@timesgroup.com

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमिटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें बंगाल सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राज्य में कानून का शासन नहीं चलता, बल्कि शासक का कानून चलता है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि जिन गांवों में हिंसा के पांच से ज्यादा मामले हुए हैं वहां सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। कमिटी ने कोलकाता हाई कोर्ट की रिपोर्ट सौंपी है। कोर्ट के आदेश के बाद ही यह कमिटी बनाई गई थी। आयोग



ने बलात्कार और हत्याओं के मामलों की जांच सीबीआई से कराने को कहा है। उनके ट्रायल राज्य से बाहर किए जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक एसआईटी का गठन किया जाए।

दिल्ली में कई नेताओं से मिलेंगी ममता

ममता बनर्जी इस महीने के आखिर में गैर-बीजेपी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। वह कई राज्यों की भी यात्रा कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, ममता सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मिलेंगी। 2024 के राष्ट्रीय चुनावों की रणनीति के तौर पर इस प्रस्तावित बैठक को देखा जा रहा है।

'Law of Ruler' in Didi's turf, says NHRC report to Calcutta High Court

EXPRESS NEWS SERVICE @ Kolkata

THE situation in West Bengal is a manifestation of 'Law of Ruler' instead of 'Rule of Law', observed the final report of the National Human Rights Commission (NHRC) on post-poll violence in the state.

The report, submitted to a five-judge bench of Kolkata High Court two days ago, also recommended that investigation of grievous offences like murder and rape should be



TMC MPs want bypolls in Bengal at the earliest

Trinamool Congress MPs (above) visited the Election Commission on Thursday, demanding immediate bypolls in six vacant Assembly seats in Bengal. Mamata Banerjee, who lost in the polls, has to get elected by November 2 to remain the CM

handed over to the CBI and tried outside the state.

The enquiry committee constituted by the NHRC also felt the spate of violence shows a pernicious 'politico-bureaucratic-criminal nexus' which is a deadly combination and has national security implications considering that West Bengal is a border state.

The Commission also found that the violence was neither sporadic nor random, instead specific persons were targeted. It also mentioned a list of notorious criminals which include

forest minister Jyotipriya Mullick and other Trinamool Congress functionaries.

Lambasting the Centre, Chief Minister Mamata Banerjee described the NHRC's report a distorted one and a conspiracy against the state. "There is no rule of law in BJP-ruled Uttar Pradesh. How many commissions visited UP? Is everything forgiven in UP because it is ruled by BJP?" said the Bengal CM.

Responding to petitions on the issue of alleged post-poll violence, the Kolkata High Court on July 2 had directed NHRC to constitute a committee and submit a report. "The situation in West Bengal is a manifestation of Law of Ruler, instead of Rule of Law. The spatio-temporal expanse of violent incidents with little efforts of state machinery to prevent or control or rectify the same is actually a large picture of organised violence by supporters of the ruling party in retribution against persons who dared to support the other major party which lost the recent Assembly elections. While some organs or personnel of the state government remained mute spectators, some others were apparently complicit," the report mentioned.

The committee made 311 spot inquiries and found that in 60 per cent of cases, FIRs were not registered, while the police resorted to dilution in 27 per cent of cases by using milder sections of law.

Citing data received from the Director General of Police (DGP), the report said 1,934 complaints were lodged with police stations and 1,168 of them were treated as FIRs. "Out of the 9,304 accused cited in the FIRs, only 1,354 (14%) have been arrested and out of these arrested, 1,086 (80%) are already out on bail.

NHRC indicts TMC leaders for Bengal post-poll violence

SAUGAR SENGUPTA ■ KOLKATA

The National Human Rights Commission probing post-poll violence in Bengal has submitted a damaging report in the Calcutta High Court underscoring the "politico-bureaucratic-criminal nexus" in Bengal. The NHRC recommended an investigation to be carried out by a Special Investigation Team of the Central Bureau of Investigation.

A five-judge Bench of the Court hearing a PIL had earlier directed the NHRC to investigate the alleged post-poll violence. The panel conducted a 20-day investigation visiting 311 spots of alleged occurrences.

Submitting a 50-page report, the seven-member NHRC team has named a bevy of senior Trinamool Congress leaders, including Ministers and legislators, in its list of "notorious criminals" — who

Mamata rejects panel's report, calls it 'vendetta politics' by Centre

directed and orchestrated attacks on Opposition supporters and voters.

Referring to a relevant quote from Tagore ("where the mind is without fear") the report concludes that Bengal is a perfect manifestation of "law of ruler" instead of "rule of law."

Chief Minister Mamata Banerjee summarily rejected the report as a "burning example of BJP's vendetta politics".

Among the senior TMC leaders indicted in the report are a Minister from North 24 Parganas, MLAs from North and South 24 Parganas, Kolkata, Birbhum, former MLAs and senior leaders from Cooch Behar, Nandigram and other places.

Continued on Page 2

NHRC indicts TMC leaders for Bengal...

From page 1

Refuting charges, a Minister from North 24 Parganas said, "There is no complaint anywhere in the State against my name and here the NHRC has recorded it in its list. I have been a member of the Bar Council and know how things work. If need be we will move the Court."

Providing details of the post poll violence, the NHRC report refers to as many as 1979 complaints from 23 districts. It said most of these complaints are from Cooch Behar, Birbhum, Burdwan, North 24 Parganas and Kolkata and a majority of them relates to rape, molestation and vandalism.

The statutory public body said that after visiting 311 spots in 20 days and carrying out an extensive inquiry in the matter, it concluded that the current situation of the State is a manifestation of "Law of Ruler", instead of "Rule of Law". It added that the loss of faith in State administration among victims is very evident. Claiming that the "violence was retributive," the

report says that "It was in retaliation to those who 'dared' to vote or support the major Opposition party. Victims were helpless and hopeless due to the torture and trauma."

Severely indicting the State police, the human rights panel writes, "Poor and common people have lost faith in Police. Almost all victims informed the Inquiry Committee that Police either did not respond to their phone calls or came and stood as mere spectators while goons went on a rampage from one place to another," dropping hints of what the State BJP leadership called "politico-bureaucratic-criminal nexus."

Saying that the current State of lawlessness could spread to other parts of the country, the report also suggests shifting of the case out of Bengal for the sake of justice.

Meanwhile, the Chief Minister attacked the Rights Commission for being a party to the BJP and the Central Government's politics of vendetta.

बंगाल में हिंसा की जांच के लिए गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपी मानवाधिकार आयोग ने कहा- चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच हो

• ममता बोलीं- समिति की
रिपोर्ट मीडिया में कै
एजेंसी | कोलकाता

विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति ने



ममता बनर्जी

गुरुवार को रिपोर्ट दे दी। कोलकाता हाइकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में हिंसा और घोटालों की दुर्दशा के

लिए राज्य सरकार को 'भयावह उदासीनता' को जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। दूसरी तरफ एक पत्रकार वार्ता में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि कोर्ट में पेश की गई यह रिपोर्ट मीडिया में कैसे आई?

ममता ने आश्चर्य जताया कि राज्य सरकार का पक्ष जाने बगैर एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) कैसे निष्कर्ष पर पहुंचा? उन्होंने 'कोर्ट का अनादर' करने और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रतिशोध का अनुसरण करने पर आयोग की तीखी आलोचना की। कहा, 'भाजपा अब राजनीतिक चहुत पाने और हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। एनएचआरसी



तृणमूल सांसद चुनाव आयोग से मिलेंगे

टीएमसी के छह सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को चुनाव आयोग से मिलने की तैयारी कर रहा है। इस मुलाकात में आयोग से राज्य की छह खाली विधानसभा सीटों पर जल्द चुनाव करने की मांग की जानी है। मशरूम शे, तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी नेदोशम से चुनाव हार गई थी। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पांच नवंबर से पहले विधायक के रूप में निर्वाचित होना है।

जुलाई अंत में दिल्ली जाएंगी ममता, गैर-भाजपा मोर्चा बनाने की चर्चा...

ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस जुलाई अंत में दिल्ली जाएंगी और अनुमति मिलने पर पीएम व राष्ट्रपति से मिलेंगी। यह भी कहा, 'मैं हर चुनाव के बाद दिल्ली जाती हूँ। पुराने और नए मित्रों से मिलती हूँ। चूंकि अभी कोरोना की स्थिति नियंत्रित है। इसीलिए इस बार भी कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ।' हालांकि तृणमूल के सूत्र बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गैर-भाजपा मोर्चा बनाए जाने की चर्चा है। लिहाजा ममता गैर-भाजपाई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता में हर साल 21 जुलाई को एक रैली करती हैं। यह रैली 1993 में इसी दिन ममता के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मारे जाने की याद में आयोजित होती है। इस आयोजन के बाद ममता 25 जुलाई को दिल्ली जा सकती हैं।

को अदालत का सम्मान करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट के जांच-निष्कर्ष मीडिया को बताने के बजाय उसे पहले अदालत में रिपोर्ट पेश

करनी चाहिए थी। यह भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध नहीं तो और क्या है? भाजपा विधानसभा चुनावों की हार अब तक नहीं पचा पाई है।

बंगाल में नहीं है कानून का राज

चुनाव बाद हिंसा मामले की जांच के बाद एनएचआरसी ने रिपोर्ट में कहा-राज्य में शासक का

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में ममता सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। 50 पन्ने की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में विश्वास खो दिया है। जांच टीम ने गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की कविता की कुछ पंक्तियों को उल्लेख करते हुए कहा है कि टैगोर की धरती बंगाल में कानून का राज नहीं, शासक का कानून चल रहा है। रिपोर्ट में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है और कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी ने राजीव जैन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया था।

गणतंत्र की हत्या हो जाएगी: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर राज्य में हिंसा नहीं रोकी गई तो भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की हत्या हो जाएगी। हिंसा दूसरे राज्यों में फैलने

गंभीर टिप्पणी

- हत्या और दुष्कर्म के मामलों की सीबीआई जांच की सिफारिश
- कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल के बड़े नेताओं के नाम, ममता के पोलिंग एजेंट का भी जिक्र
- सुनवाई को राज्य के बाहर फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने की अनुशंसा

रिपोर्ट लीक होने पर भड़की ममता

ममता बनर्जी ने कहा, यह बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। एनएचआरसी ने विकृत रिपोर्ट पेश की है। पीएम मोदी ने उप्र में जांच के लिए कितने कमीशन भेजे? हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हो चुकी हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट लीक कर दी। उसे कोर्ट का सम्मान करना चाहिए।

लगेगी। जांच के दौरान दुष्कर्म, हत्या, आगजनी जैसे सैकड़ों मामले सामने आए, जिनकी शिकायतें दर्ज नहीं की गई हैं। पुलिस पर लोगों को विश्वास नहीं है, उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही हैं। समिति को मिली शिकायतों को पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है, ताकि प्राथमिकी दर्ज हो। ज्यादातर मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, अगर कुछ गिरफ्तारियां हुईं भी तो आरोपित जमानत पर रिहा हो गए। वहीं,

बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओं से पीड़ितों के प्रति राज्य सरकार की भय उत्पन्न करने वाली उदासीनता दिखाई देती है।
-रिपोर्ट का एक अंश (आइएनएस के अनुसार)



1,900 से अधिक शिकायतें मिलीं जांच टीम को दुष्कर्म, हत्या, आगजनी से जुड़ी

समिति में शामिल थे ये सदस्य

एनएचआरसी की जांच समिति में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अतीफ रशीद, महिला आयोग की डा. राजुबेन देसाई, एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) संतोष मेहरा, बंगाल मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, राज्य लीगल सर्विस कमीशन के सचिव राजू मुखर्जी और महानिरीक्षक मजिल सेनी शामिल थीं।

आइएनएस के अनुसार, अधिकांश आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं।

जांच की मानिट्रिंग करे कोर्ट: रिपोर्ट के अनुसार, हत्या और दुष्कर्म के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सुनवाई राज्य के बाहर हो। हिंसा में अन्य गंभीर अपराधों के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया जाए, जिसकी मानिट्रिंग कोर्ट करे। रिटायर्ड जज की देखरेख में मानिट्रिंग कमेटी बने और हर जिले

में एक स्वतंत्र अफसर आब्जर्वर के रूप में तैनात किया जाए। जांच का आदेश जल्दी हो, क्योंकि दिन-ब-दिन स्थिति खराब होती जा रही है। पीड़ितों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ पुनर्वास, सुरक्षा और आजीविका की भी व्यवस्था कराई जाए।

कुख्यात अपराधियों में ये बड़े नेता: रिपोर्ट के अनुसार कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल सरकार में मंत्री

रिपोर्ट के प्रमुख

- 9,304 पर प्राथमिकी, 1,354 गिरफ्तार, 97 आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं
- दबाव में पुलिस नहीं कर शिकायतों पर कार्रवाई मामलों के लिए एसआर
- विशेष लोक अभियोजन नियुक्त करने और ग
- सुरक्षा देने की बात
- केंद्रीय बलों की तैनाती के पुनर्वास पर भी हो
- हिंसा के मामलों में ल
- वरतने वाले अफसरों सख्त कार्रवाई हो

ज्योतिप्रिय मल्लिक, विधायक शोभा भूमिक, विधायक शोभा विधायक खोकन दास, जीवन साहा, उदयन गुप्ता में ममता बनर्जी के पोलि शेख सुफियान समेत नेताओं के नाम हैं। ह नेताओं ने कहा है कि केंद्र बदले की भावना से रिप नाम दिया गया है।

Political vendetta: Mamata hits out at NHRC for 'leaking' report over post-poll violence in Bengal

OUR CORRESPONDENT

KOLKATA: Chief Minister Mamata Banerjee on Thursday lashed out at the National Human Rights Commission (NHRC) after its committee, probing alleged incidents of post-poll violence in the state, accused the state government of showing "appalling apathy" towards the victims of the post-poll violence.

Banerjee accused the committee of leaking its probe report to media and called the move a "political vendetta."

"The NHRC should have respected the court. Instead of leaking the findings to the

media, it should have first submitted the same to the court," she said.

She further said she is well aware of those who submitted the report. "If you ask me to give details about those people, I will say that the court will state their identity," Banerjee said.

She also hit out at the BJP for giving "biased statements" in connection with the subjudice matter.

The Chief Minister also maintained that her government will file a response when the court asks them to. She accused Prime Minister Narendra Modi of 'maligning' the state, "using impartial agencies

to settle political scores." "What would you call it other than political vendetta of the BJP? It is yet to digest defeat (in the Assembly polls) and that is why the party is resorting to such tricks," Banerjee said.

The NHRC panel has recommended a CBI inquiry into "grievous offences like murder and rape," in its report to the Calcutta High Court, adding that the cases should be tried outside of the state.

The NHRC committee constituted by its chairperson had submitted a report before the High Court on cases of alleged human rights violations in post-poll violence on June 13.

The TMC leader also hit out at the situation of law and order in Uttar Pradesh. "Modi knows very well that there is no rule of law in UP. How many human rights commission has he sent there?... So many incidents, from Hathras to Unnao, have taken place," she said. She maintained that the central agency is maligning Bengal and said that the violence took place before the polls were held when the law and order was under the Election Commission. The leaked NHRC report mentioned some of the senior leaders as "notorious criminals" and also recommended cases to be probed by the CBI.

Continued on P4

Mamata hits out at NHRC

Commenting on the same, MP Kalyan Banerjee said: "The report is full of lies and there is not an iota of truth in it. The NHRC did not visit the houses of Trinamool Congress supporters who had been beaten up by BJP activists during the election. Not a single untoward incident happened after Mamata Banerjee took oath for the third consecutive time as the Chief Minister on May 5. The incidents took place at a time when the law and order was under the Election Commission."

State Forest minister Jyotipriya Mallick said: "I challenge such allegations. There is not even a single general diary against my name in any police station. All these are nothing but BJP's vendetta politics. If needed, a defamation suit will also be filed."

Udayan Guha, Jiban Saha, Sheikh Sufiyan, Jyotipriya Mallick, Partha Bhowmick and Shaikat Mollah have been named as "notorious criminals" in the report.

Meanwhile, the NHRC on Thursday rejected as "baseless and factually incorrect" allegations that a report prepared by its committee probing the incidents of post-poll violence in Bengal has been leaked by the rights panel.

It said in a statement that the panel had submitted its report to the Calcutta High Court on July 13.

Since the report is already available with all the concerned parties as per the directives of the court,

"there is no question of leakage at the level of the NHRC," the rights panel said.

बंगाल चुनाव हिंसा : बलात्कार हत्या मामलों की हो CBI जांच

■ कोलकाता (भाषा) ।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) समिति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार पर बेहद तल्लख टिप्पणी करते हुए राज्य में स्थिति को 'कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन' करार दिया तथा 'हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों' की जांच सीबीआई से कराए जाने और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की है। वहीं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाबी हमला किया और एनएचआरसी पर भाजपा के 'राजनीतिक प्रतिशोध' पर चलने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि रिपोर्ट लीक की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है। एनएचआरसी समिति ने अपनी बेहद तल्लख टिप्पणी में कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा यह हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संलग्नकों के साथ 'सॉफ्ट' प्रतियां याचिकाकर्ताओं-याचिकाकर्ताओं के वकील, निर्वाचन आयोग और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सौंपी जाएं।

घटनाक्रम पर बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में दावा किया कि मानवाधिकार आयोग ने मीडिया को रिपोर्ट लीक



(फाइल फोटो)

■ एनएचआरसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में की सिफारिश

■ राज्य में स्थिति को 'कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन' करार दिया

■ ममता बनर्जी ने एनएचआरसी पर भाजपा के 'राजनीतिक प्रतिशोध' पर चलने का आरोप लगाया

की है। उन्होंने यह भी कहा कि एनएचआरसी की टीम ने राज्य सरकार से मशविरा नहीं किया और न ही उसके मत को संज्ञान में लिया। बनर्जी ने कहा, भाजपा अब राजनीतिक लाभ के लिए और हमारे राज्य की छवि खराब करने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। एनएचआरसी को अदालत का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, यदि आप इसे भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध नहीं तो और क्या कहेंगे? अभी वह (विधानसभा चुनाव) हार को नहीं पचा पाई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है।

NHRC panel seeks CBI probe into Bengal riots

Report cites cases of murder, rape and molestation

DAMINI NATH
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) committee formed to investigate complaints of post-poll violence in West Bengal has recommended that cases of heinous crimes be transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI).

In its report to the Calcutta

High Court on Monday, the panel said it received 1,979 complaints covering over 15,000 victims during its inquiry. The panel visited the State from June 24 to July 10. "A large number of cases related to murders, rapes, molestation and vandalism received from local sources in West Bengal while the teams were camping there," the report said.

The Calcutta High Court-ordered panel, which was headed by NHRC member Rajiv Jain, concluded that

the State government had exhibited apathy towards the victims. It found that there was "retributive violence" by Trinamool Congress supporters against supporters of the "major Opposition party", referring to the BJP.

'Hold trial outside State'

"There is need to provide justice to victims and restore their confidence in the criminal justice system, which can be best rendered by a neutral agency. Hence, it is recommended that all heinous

cases, including murder, unnatural deaths, rape and grievous hurt, and complaints carrying these allegations, should be transferred to the CBI for investigation," the report said, adding that the trial of the CBI cases should be conducted outside West Bengal.

The report said there had been 29 complaints related to murder and 12 cases of attempt to rape/sexual assault/molestation.

CONTINUED ON ► PAGE 8

NHRC panel seeks CBI probe into Bengal riots

The panel concluded that the police and government officials had been found lacking. "It is quite evident that police is working under influence and in a biased manner and do not have the courage to take action against looming goons belonging to the ruling dispensation," the report said.

The panel said out of the 9,304 people accused in the cases, only 14% had been arrested.

The committee also added that it found victims hesitant to speak during its 311 spot visits in the State, with some even reporting being threatened after meet-

ing with the NHRC teams.

"Several victims also complained that they were being discriminated against in getting vaccination for COVID-19 because they were perceived to be supporters of the main Opposition party," the report said.

Among the heinous crimes alleged following the completion of Assembly election in May, the panel said women in Kenbona village reported that "police along with Trinamool Congress goons broke into their houses at midnight" on May 23 and they were taken into custody "in semi-nude condition".

NHRC recommends CBI probe into Bengal post-poll violence

Rights panel disrespected court, shouldn't have leaked report to media: Didi

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, JULY 15

The seven-member committee constituted by the National Human Rights Commission (NHRC) in pursuance of order by the Calcutta High Court to look into the complaints of post-poll violence in West Bengal has said in its report that there is "Law of ruler" instead of "Rule of law" in the state and recommended CBI probe into heinous cases.

Contents of the committee's final report, submitted in the High Court on July 13, surfaced on Thursday.

Underscoring the need to provide justice to victims and to restore their confidence in the criminal justice system, the report recommended that all heinous cases, including murder, unnatural deaths,



Trinamool Congress delegation members after a meeting with the CEC in New Delhi on Thursday. TRIBUNE PHOTO: MUKESH AGGARWAL

TMC MPs MEET EC PANEL TO PRESS FOR EARLY POLL

New Delhi: A six-member team of TMC MPs on Thursday met the Chief Election Commissioner (CEC) and his deputies here and requested the officials to urgently hold elections in seven vacant Assembly seats of Bengal. TMC leader Sudip Bandyopadhyay said they were happy with the way the CEC responded to their appeal. "His response has filled us with hope," he added. TNS

Mamata writes to PM on increasing vax supply

rape and grievous hurt should be transferred to the CBI for investigation.

It further said trial of the cases investigated by the CBI should be held outside West Bengal. The report also recommended a court-monitored special investigation team (SIT) to look into some of the cases of post-poll violence.

Violence was perpetrated by ruling party supporters, the panel found. The next hearing of the case is slated to take place on July 22.

Chief Minister Mamata Banerjee flayed the NHRC for "disrespecting the court" and pursuing "political vendetta" of the BJP by leaking its report to the media. She also announced she would visit Delhi next week after the commencing of the Parliament session and try to meet the PM and President.

NHRC panel seeks CBI probe into Bengal riots

Report cites cases of murder, rape and molestation

DAMINI NATH
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) committee formed to investigate complaints of post-poll violence in West Bengal has recommended that cases of heinous crimes be transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI).

In its report to the Calcutta

High Court on Monday, the panel said it received 1,979 complaints covering over 15,000 victims during its inquiry. The panel visited the State from June 24 to July 10. "A large number of cases related to murders, rapes, molestation and vandalism received from local sources in West Bengal while the teams were camping there," the report said.

The Calcutta High Court-ordered panel, which was headed by NHRC member Rajiv Jain, concluded that

the State government had exhibited apathy towards the victims. It found that there was "retributive violence" by Trinamool Congress supporters against supporters of the "major Opposition party", referring to the BJP.

'Hold trial outside State'

"There is need to provide justice to victims and restore their confidence in the criminal justice system, which can be best rendered by a neutral agency. Hence, it is recommended that all heinous cases, including murder, unnatural deaths, rape and grievous hurt, and complaints carrying these allegations, should be transferred to the CBI for investigation," the report said, adding that the trial of the CBI cases should be conducted outside West Bengal.

The report said there had been 29 complaints related to murder and 12 cases of attempt to rape/sexual assault/molestation.

CONTINUED ON ► PAGE 10

NHRC panel seeks CBI probe into Bengal riots

The panel concluded that the police and government officials had been found lacking. "It is quite evident that police is working under influence and in a biased manner and do not have the courage to take action against looming goons belonging to the ruling dispensation," the report said.

The panel said out of the 9,304 people accused in the cases, only 14% had been arrested.

'Women threatened'

The committee also added that it found victims hesitant to speak during its 311 spot visits in the State, with some even reporting being threatened after meeting with the NHRC teams.

"Several victims also complained that they were being discriminated against in getting vaccination for COVID-19 because they were perceived to be supporters of the main Opposition party," the report said.

Among the heinous crimes alleged following the completion of Assembly election in May, the panel said women in Kenbona village reported that "police along with Trinamool Con-

gress goons broke into their houses at midnight" on May 23 and they were taken into custody "in semi-nude condition".

"The spate of violence shows a pernicious politico-bureaucratic-criminal nexus. Criminals indulged in violence against political rivals while the bureaucratic edifice was complicit in various degrees... The presence of this nexus in a border State also has larger national security implications," the panel said.

The panel recommended setting up a court-monitored Special Investigation Team (SIT) to register cases and investigate them. It also said the State government should formalise its witness protection scheme.

"If the above mentioned worrisome trend is not arrested, where the entire might of the governmental machinery has been used [through innumerable acts of omission and commission] for furthering the political objectives of the party in power, the disease may spread to other States also. This may well be death knell for democracy in this great nation," the report said.

'NHRC report political vendetta against WB'

We Should Have Been Allowed To Respond To Report: Didi

Debashis.Konar
@timesgroup.com

Kolkata: Trinamool seniors on Thursday reacted to the NHRC panel's "findings", saying such reports were natural when "BJP activists become NHRC members". Bengal CM Mamata Banerjee said that she knew "the people who submitted the report".

"Only the court will give their identity," Banerjee said, adding that she had the highest respect for the court. "I will abide by the court verdict. This is a sub-judice matter. They have leaked it instead of submitting the report in court," she said, calling the "leak" an act of "political vendetta to malign the people of Bengal". "The state government should have been allowed to respond (to the NHRC report). The court has



“ I will abide by the court verdict. This is a sub-judice matter. They have leaked it instead of submitting the report in court

MAMATA BANERJEE
Bengal Chief Minister

asked the state to give its opinion and it will be done in the form of an affidavit," Banerjee said. "Uttar Pradesh is out of rule of law. UP is their baby, so it's safe?" she said, accusing PM Narendra Modi of distorting facts and misleading people. Banerjee refused to respond directly to the NHRC panel's accusations but many of her colleagues were more blunt.

"The report is exaggerated," Trinamool MP Saugata Roy said, adding: "What else do you expect if BJP activists

become (NHRC) committee members?"

NHRC committee members were giving statements to the media questioning the police's role even before they had submitted their report to the court, another Trinamool MP said, concluding that it was expected that the "report" would reflect their "views and not findings". "What else will one expect when local BJP leaders guided NHRC committee members to the 'trouble' spots?" the MP asked.

Full report on www.toi.in

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा / हाईकोर्ट में रिपोर्ट

एनएचआरसी ने सीबीआई जांच को कहा

कोलकाता, 15 जुलाई (एजेसी)

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। समिति ने बेहद तल्ख टिप्पणी में कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा यह हिंसा, मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई। रिपोर्ट में राज्य में स्थिति को 'कानून के शासन की जगह शासक के शासन का प्रदर्शन' करार दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है।



हथकंडे अपना रही भाजपा : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनएचआरसी की रिपोर्ट लीक किये जाने को अदालत का अपमान बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाये। ममता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'भाजपा अब हमारे राज्य की छवि खराब करने और राजनीतिक बदला लेने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का सहारा ले रही है। एनएचआरसी को अदालत का सम्मान करना चाहिए था। मीडिया में रिपोर्ट के निष्कर्ष लीक करने के बजाय, उसे पहले इसे अदालत में दाखिल करना चाहिए था।' उन्होंने कहा, 'आप इसे भाजपा के राजनीतिक बदले के अलावा और क्या कहेंगे? वह अब भी हार पचा नहीं पाई है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है।'

अदालत को 13 जून को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, 'समिति ने सिफारिश की है कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलना चाहिए।' गौर हो कि हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ के

निर्देश पर एनएचआरसी अध्यक्ष ने यह समिति गठित की है। हाईकोर्ट में दायर कई जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में लोगों पर हमले किए गये, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया।

BENGAL VIOLENCE**Mamata hits back after NHRC's scathing report**

AGENCIES

Kolkata, July 15: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee Thursday flayed the NHRC for "disrespecting the court" and pursuing "political vendetta" of the BJP by leaking its report on alleged post-poll violence in the state to the media.

Banerjee also expressed surprise over the conclusion that the National Human Rights Commission arrived at in its report without taking into account views of the state government.

"The BJP is now using impartial agencies to settle political scores and malign our state. The NHRC should have respected the court. Instead of leaking the findings to the media, it should have first submitted the same to the court.

"What would you call it other than political vendetta of the BJP? It is yet to digest defeat (in the assembly polls) and that is why the party is resorting to such tricks," she told a press conference here.

Asserting that the situation in West Bengal is a "manifestation of law of ruler instead of rule of law", an NHRC committee probing alleged incidents of post-poll violence in the state, in a report placed before the Calcutta High Court, recommended a CBI probe into "grievous offences like murder and rape".

Banerjee said she has the highest regard for the judiciary and her government will present "its views and versions in the court".

"The pre-poll violence when the election commission was in charge (of state affairs) is being presented as post-poll violence," the chief minister claimed.

She also wondered how many human rights commission teams were sent to Uttar Pradesh, which has reported cases of attacks on minorities over the last few years.

Criticising Modi for lauding the UP government for its fight against Covid-19, Banerjee said his statement is "biased" and untrue.

NHRC indicts TMC leaders for Bengal post-poll violence

SAUGAR SENGUPTA ■ KOLKATA

The National Human Rights Commission probing post-poll violence in Bengal has submitted a damaging report in the Calcutta High Court underscoring the “politico-bureaucratic-criminal nexus” in Bengal. The NHRC recommended an investigation to be carried out by a Special Investigation Team of the Central Bureau of Investigation.

A five-judge Bench of the Court hearing a PIL had earlier directed the NHRC to investigate the alleged post poll violence. The panel conducted a 20-day investigation visiting 311 spots of alleged occurrences.

Submitting a 50-page report, the seven-member NHRC team has named a bevy of senior Trinamool Congress leaders, including Ministers and legislators, in its list of “notorious criminals” — who

Mamata rejects panel’s report, calls it ‘vendetta politics’ by Centre

directed and orchestrated attacks on Opposition supporters and voters.

Referring to a relevant quote from Tagore (“where mind is without fear”) the report concludes that Bengal is a perfect manifestation of “law of ruler” instead of “rule of law.”

Chief Minister Mamata Banerjee summarily rejected the report as a “burning example of BJP’s vendetta politics”.

Among the senior TMC leaders indicted in the report are a Minister from North 24 Parganas, MLAs from North and South 24 Parganas, Kolkata, Birbhum, former MLAs and senior leaders from Cooch Behar, Nandigram and other places.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा- बंगाल में कानून का शासन नहीं

समिति बोली- चुनाव बाद
हिंसा की सीबीआई जांच हो
कोलकाता | बंगाल में विधानसभा
चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के
लिए बनी राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग (एनएचआरसी) की
समिति ने रिपोर्ट दे दी है। इसमें
राज्य की ममता बनर्जी सरकार
और सत्ताधारी दल- तृणमूल
कांग्रेस (टीएमसी) पर कड़ी
टिप्पणियां की गई हैं। रिपोर्ट के
मुताबिक, 'बंगाल में कानून का
राज नहीं, बल्कि शासक का कानून
चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के
समर्थकों ने यह हिंसा मुख्य विपक्षी
दल (भारतीय जनता पार्टी) के
समर्थकों को सबक सिखाने के
लिए की।' आयोग की समिति ने
13 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट
को 50 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है।
इसमें चुनाव बाद हिंसा की जांच
सीबीआई से कराने की सिफारिश
की गई है। दूसरी तरफ गुरुवार
को एक पत्रकार वार्ता में राज्य की
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल
उठाया कि कोर्ट में पेश की गई यह
रिपोर्ट मीडिया में कैसे आई? ममता
ने आश्चर्य जताया कि राज्य सरकार
का पक्ष जाने बगैर एनएचआरसी
कैसे निष्कर्ष पर पहुंचा?

NHRC indicts Mamata govt over post-poll violence

The situation prevailing in West Bengal is a manifestation of "law of the ruler" and not "rule of law", the NHRC panel probing alleged post-poll violence in the state has said in a damning indictment of the Mamata Banerjee government, and recommended CBI investigation in cases of rape and murder.

A livid Banerjee accused the National Human Rights Commission (NHRC) of pursuing BJP's "political vendetta" and claiming the report was "leaked".

The NHRC panel, constituted following an order by a five-judge bench of the Calcutta High Court, also said the cases of alleged rape and murder be tried outside the state.

"The committee has recommended that grievous offences like murder, rape, etc., should be handed over to the CBI for investigation and these cases should be tried outside the state," the report, submitted to the court in sealed covers on June 13, said.

The court had directed that its soft copies along with annexures be supplied to the counsel for the petitioners, the Election Commission, and the Additional Solicitor General of India.

Banerjee cried foul and claimed the report was leaked to the media by the rights panel. She said the NHRC team did not take into account the state government's views.

NHRC report slams TMC govt on post-poll violence

SOUMYA DAS
KOLKATA, DHNS

The National Human Rights Commission (NHRC) submitted a scathing final report on post-poll violence in West Bengal to the Calcutta High Court stating that “rule of the ruler” was prevailing in the state instead of the rule of law.

It stated that if the situation continues to prevail in Bengal, “it may very well be the death knell for democracy in this great nation”. It also stated that the continuation of violent incidents in Bengal



Mamata Banerjee

shows “abject failure” of the state government.

The 50-page report stated that most of the violent incidents such as murder, rape, molestation, assault, were “neither sporadic nor random” but “targeted specific

persons” associated with the main Opposition party.

“Violence was retributive. It was in retaliation to those who ‘dared’ to vote or support the major opposition party,” stated the report.

Reacting to the development, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said the BJP was using “impartial agencies to settle political scores and malign Bengal”. The NHRC should have respected the court. Instead of leaking the report to the media, it should have submitted it to the court first,” she said.

It's law of ruler, not rule of law in Bengal, says NHRC

Subrata Chattoraj@timesgroup.com

Kolkata: In a scathing indictment of the West Bengal government, National Human Rights Commission's panel examining post-poll violence complaints has said that "the law of the ruler" exists in the state "instead of the rule of law".

The panel, which was asked to examine the complaints by a five-judge bench of the Calcutta High Court, has recommended in its final report that complaints of "grievous offences like rape and murder" be handed over to the CBI for investigation. "These cases should be tried outside the state. The other cases should be investigated by a court-monitored special investigation team. There should be fast-track courts, a special public prosecutor and a witness-protection scheme," the report stated.

The panel provided a list of 13 "delinquent police stations" in

Coochbehar, Birbhum, South 24 Parganas, North 24 Parganas and Howrah where the number of arrests was the lowest and recommended action against "delinquent government servants".

The Bengal government has already filed a "recall application" in the Calcutta High Court, seeking modification of the five-jud-

'SHIFT POST-POLL VIOLENCE CASES'

ge bench's order as the court gave additional directions to the state government based on the NHRC team's "brief report" even though the state did not have access to the contents of the report.

The state had also objected to the larger bench's recording of its response to post-poll complaints as "lukewarm". "The findings in the interim report are required to be supported by evidence and rea-

sons," the state application stated.

The NHRC report comes at a time when the Supreme Court has issued notices to the Election Commission, the Centre and the Bengal government following a PIL urging President's rule in Bengal.

The 50-page report noted the state government's "appalling apathy" to victims' plight, adding: "The spate of violence shows a pernicious politico-bureaucratic-criminal nexus. This was retributive violence by supporters of the ruling party against supporters of the main opposition party. It resulted in disruption of life and livelihood of thousands of people and their economic strangulation. The local police have been grossly derelict if not complicit in this violence." NHRC panel members made 311 spot visits in 20 days and held "camp sittings" in Kolkata, East Midnapore, Howrah, East Burdwan and Murshidabad.

Mamata: BJP men part of NHRC, report is vendetta

Debashis.Konar@timesgroup.com

Kolkata: Trinamool seniors on Thursday reacted to the NHRC panel's "findings", saying such reports were natural when "BJP activists become NHRC members". Bengal CM Mamata Banerjee said that she knew "the people who submitted the report".

"Only the court will give their identity," Banerjee said, adding that she had the highest respect for the court. "I will abide by the court verdict. This is a sub-judice matter. They have leaked it instead of submitting the report in co-

urt," she said, calling the "leak" an act of "political vendetta to malign the people of Bengal".

"The state government should have been allowed to respond (to the NHRC report). The court has asked the state to give its opinion and it will be done in the form of an affidavit," Banerjee said. "Uttar Pradesh is out of rule of law. UP is their baby, so it's safe?" she said, accusing PM Narendra Modi of distorting facts and misleading people.

Mamata Banerjee refused to respond directly to the NHRC panel's accusations.



NHRC panel seeks CBI probe into Bengal riots

Report cites cases of murder, rape and molestation

DAMINI NATH
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) committee formed to investigate complaints of post-poll violence in West Bengal has recommended that cases of heinous crimes be transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI).

In its report to the Calcutta

High Court on Monday, the panel said it received 1,979 complaints covering over 15,000 victims during its inquiry. The panel visited the State from June 24 to July 10. "A large number of cases related to murders, rapes, molestation and vandalism received from local sources in West Bengal while the teams were camping there," the report said.

The Calcutta High Court-ordered panel, which was headed by NHRC member Rajiv Jain, concluded that

the State government had exhibited apathy towards the victims. It found that there was "retributive violence" by Trinamool Congress supporters against supporters of the "major Opposition party", referring to the BJP.

'Hold trial outside State'

"There is need to provide justice to victims and restore their confidence in the criminal justice system, which can be best rendered by a neutral agency. Hence, it is recommended that all heinous cases, including murder, unnatural deaths, rape and grievous hurt, and complaints carrying these allegations, should be transferred to the CBI for investigation," the report said, adding that the trial of the CBI cases should be conducted outside West Bengal.

The report said there had been 29 complaints related to murder and 12 cases of attempt to rape/sexual assault/molestation.

CONTINUED ON ► PAGE 10

NHRC panel seeks CBI probe into Bengal riots

The panel concluded that the police and government officials had been found lacking. "It is quite evident that police is working under influence and in a biased manner and do not have the courage to take action against looming goons belonging to the ruling dispensation," the report said.

The panel said out of the 9,304 people accused in the cases, only 14% had been arrested.

'Women threatened'

The committee also added that it found victims hesitant to speak during its 311 spot visits in the State, with some even reporting being threatened after meeting with the NHRC teams.

"Several victims also complained that they were being discriminated against in getting vaccination for COVID-19 because they were perceived to be supporters of the main Opposition party," the report said.

Among the heinous crimes alleged following the completion of Assembly election in May, the panel said women in Kenbona village reported that "police along with Trinamool Con-

gress goons broke into their houses at midnight" on May 23 and they were taken into custody "in semi-nude condition".

"The spate of violence shows a pernicious politico-bureaucratic-criminal nexus. Criminals indulged in violence against political rivals while the bureaucratic edifice was complicit in various degrees... The presence of this nexus in a border State also has larger national security implications," the panel said.

The panel recommended setting up a court-monitored Special Investigation Team (SIT) to register cases and investigate them. It also said the State government should formalise its witness protection scheme.

"If the above mentioned worrisome trend is not arrested, where the entire might of the governmental machinery has been used [through innumerable acts of omission and commission] for furthering the political objectives of the party in power, the disease may spread to other States also. This may well be death knell for democracy in this great nation," the report said.